प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

शिमला से प्रकाशित

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक-39 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 19-26 सितम्बर 2022 मूल्य पांच रूपए

क्या 2541.43 करोड़ के ऋण लाभार्थीयों की सूची जारी हो पायेगी? मुख्यमन्त्री की चुनाव घोषणाओं से उठी चर्चा

- क्या दूसरे दलों में तोड़ फोड़ से ही हो जायेगी सत्ता में वापसी
- धूमल समर्थकों की नाराजगी का क्या होगा परिणाम

शिमला/शैल। क्या भाजपा कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करके ही सत्ता में वापसी कर पायेगी? क्या मुख्यमंत्री द्वारा चुनावों से पहले हर विधानसभा क्षेत्र में की जा रही करोड़ों की घोषणाओं से ही जनता प्रभावित हो जायेगी? ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय चर्चा और आकलन का विषय बनते जा रहे हैं क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और कांगड़ा से कांग्रेस के

कार्यकारी अध्यक्ष विधायक पवन काजल को भाजपा में शामिल करवा दिया। इन दोनों के शामिल होने के बाद यह सामने आया है कि इतने बड़े राजनीतिक फैसले से पहले न तो वहां के मण्डलों से और न ही जिला संगठन को इस बारे में विश्वास में लिया गया। उल्टे यह सामने आया कि यह धूमल खेमे को हाशिये पर धकेलने का एक सुनियोजित प्रयास है। इससे पूर्व मंत्री रविन्द्र रवि जो देहरा से सीधे प्रभावित हो रहे थे उनकी नाराजगी एकदम बाहर आ गयी। वह किस्सा फिर एक राजनीतिक मुद्दा बनकर चर्चा का विषय बन गया जो वक्त के साथ शान्त हो चुका था। स्वास्थ्य विभाग की वर्किंग को लेकर जो खुला पत्र किसी कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार के नाम लिखा था उसमें उठाये मुद्दों की जांच करने की बजाय उस पत्र के लेखक को खोजने में सरकार की एजैन्सियां व्यस्त हो गयी। यह तलाश रविन्द्र रवि के खिलाफ मामला दर्ज करने तथा उनका मोबाइल जब्त करने के साथ रुकी। लेकिन यह जांच इस पड़ाव से आज तक आगे नहीं बढ़ी है। अदालत में चालान कब दायर होगा यह शायद जांच एजैन्सी को भी पता नहीं है। लेकिन इस प्रकरण से जो राजनीतिक ज्वाला सुलगी है वह राजनीतिक हवा के हर झोंके से तेज होती जा रही है। रविन्द्र रवि की नाराजगी खुलकर सामने आ गयी है। रवि के इन सारे प्रयासों को उनके राजनीतिक वजूद को खत्म करने का षडयन्त्र करार दिया है। रविन्द्र रवि के साथ ही जोगिन्दर नगर के पूर्व मंत्री गुलाब सिंह निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा के भाजपा में आने से प्रभावित हुये हैं। इन प्रयासों को धूमल को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के षडयन्त्र के रूप में देखा जा रहा है। इससे धूमल समर्थकों में नाराजगी होना स्वभाविक है। इसी नाराजगी का परिणाम है कि सुजानपुर में राज्यसभा सांसद इन्दु गोस्वामी धूमल को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील कर गयी। हमीरपुर में बाकायदा पत्रकार वार्ता में दर्जी भाई ने यह ऐलान कर दिया है कि यदि धूमल को पार्टी हमीरपुर से चुनाव नहीं लड़वाती है तो वह हर हालत में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस प्रकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि धूमल समर्थकों का रोष इस बार चुनावों में पार्टी पर भारी पड़ेगा। कांगड़ा में पवन काजल के आने का स्वागत नहीं हुआ है। इसका सीधा प्रभाव धर्मशाला सीट पर भी पड़ रहा है। धर्मशाला में मौजूदा विधायक का टिकट काटे जाने की चर्चाओं के बीच संघ भाजपा के आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार टिकट की दौड़ में सामने आ गये हैं। इसी के साथ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूरे जिले का बजट केवल सुलह विधानसभा क्षेत्र में ही दे दिया गया जाना भी अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है इसी परिपेक्ष में आज मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही चुनाव पूर्ण घोषणाओं पर भी सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि 31 मार्च 2019 को आयी कैग रिपोर्ट में सरकार को नये पूंजीगत कार्यो की अनुमति पर सीलिंग लगाने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर दिये गये थे। कैग रिपोर्ट में कहा है कि

(i) To Provide for the statutory flexible limits on fiscal deficit.

(ii) To Provide a statutory ceiling on the sanction of new capital works to an appropraite multiple of the annual budget provision.

लेकिन इन निर्देशों के अनुपालन में 2019-20 में शिक्षा के बजट में 1.39% की कटौती कर दी गयी और प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना में लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में सितम्बर 2019 तक 2541.43 करोड़ के ऋण बांट दिये गये। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाया गया है। सभी बैंक शाखाओं को यह ऋण देने के निर्देश दिये गये थे। लेकिन इस ऋण सुविधा का कितने लाभार्थियों ने सही उपयोग किया है इसमें से कितना ऋण अब तक वापस आ गया है इसकी कोई सूची अब तक जारी नहीं हो पायी है। क्या यह जनता के पैसे का सही उपयोग है यह सवाल उठना शुरू हो गया है।

यह है आर्थिक सर्वेक्षण में दर्ज उपलब्धि

5.16 बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में सितम्बर, 2019 तक चालू वित्त वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत 17,562 नए लघु उद्यमियों को ₹425.19 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। सितम्बर, 2019 तक पी.एम.एम.वाई. के अन्तर्गत 1,45,838 उद्यमियों को ₹2,541.43 करोड़ के ऋण वितरित करते हुए बैंकों की संचयी स्थिति है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-हिन्दी और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए एक वरदान विषय पर सेमिनार आयोजित

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि देश के विकास में मातृभाषा की भूमिका महत्वपूर्ण

है। उन्होंने कहा कि यदि भारत विश्व गुरू बनना चाहता है तो हमें अपनी मातृभाषा में कार्य करना होगा।

राज्यपाल 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – हिन्दी और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए एक वरदान' विषय पर हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षण मंडल के प्रचार विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कांगड़ा जिला के धर्मशाला में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी शिक्षा व्यवस्था को उपनिवेशवाद से छुटकारा दिलाने का पहला प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस नीति से युवा रोजगार प्रदाता बनेंगे न कि रोजगार चाहने वाले। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें स्व अक्षर का बोध करवाती है जिसका तात्पर्य है कि हमारा राष्ट्र और हमारी संस्कृति एवं हमारा इतिहास, जो कुछ है वह मेरा अपना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह जागृति लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि यदि स्व जागृत होता है तो कोई भी हमें विश्व गुरू बनने से नहीं रोक सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान शिक्षा नीति हमें केवल नौकरी ढूंढने वाला बनाती है न कि रोजगार प्रदाता। यह युवाओं को अपनी मातृभूमि से नहीं जोड़ पाती जबकि इसके विपरित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें सही राह पर चलने की दिशा दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत का गौरवशाली इतिहास एवं संस्कृति रही है। राजनीतिक आजादी प्राप्त करने के उपरान्त विश्व की हमसे विशेष अपेक्षाएं थी, परन्तु हमने दूसरे देशों की ओर देखना आरम्भ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम विश्व को दिशा दिखा सकते थे लेकिन हमने अपना गौरवशाली इतिहास भूल चुके थे। उन्होंने कहा कि इसका कारण अंग्रेजों से प्रभावित होना था। उन्होंने कहा कि कई वर्षो के उपरान्त नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें सही राह दिखाई है।

भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री मुकुल कानितकर ने कहा कि अंग्रेजों ने 1835 में देश की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने का षड़यंत्र रचा जबकि उस समय देश की साक्षरता दर लगभग शत – प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा भी अंग्रेजों के ही एक सर्वेक्षण में सामने आया था। उन्होंने कहा कि अब इसके 185 वर्षो के उपरांत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है जो कि वास्तव में भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों को रेखांकित करती है। यह हमें समान अधिकार प्रदान करती है और क्षेत्रीय भाषाओं को भी मान्यता देती है। उन्होंने कहा कि भारत में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा और बोली राष्ट्रीय भाषा थी, परन्तु बिना किसी संवैधानिक संशोधन के अंग्रेजी ने अभी तक अपना प्रभुत्व बनाए रखा है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद वाले सभी विकसित देशों ने अपनी भाषा को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें ऐसे अवसर दिए हैं जिनका हम सभी को लाभ उठाने की आवश्यकता है।

इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा – निर्देश तैयार किए और इस नीति को लागू किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय संस्कृति से जुड़ने का ठोस प्रयास किया गया है और पहली बार अपनी भाषा को महत्व देने का प्रयास हुआ है।

आरोग्यता के लिए आधुनिक और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का समावेश अत्यंत आवश्यक:आर्लेकर

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि देश के सभी नागरिकों की आरोग्यता सुनिश्चित करने तथा उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए

आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ – साथ भारत के आयुर्वेद, योग और अन्य प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का समावेश किया जाना चाहिए। अलग – अलग चिकित्सा पद्धतियों में कार्य कर रहे चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए तथा एक – दूसरे की चिकित्सा पद्धति को पूरा सम्मान देना चाहिए। राज्यपाल राजभवन में आरोग्य भारती की हिमाचल प्रदेश इकाई द्वारा 'एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य तंत्र' विषय पर आयोजित एक परिसंवाद में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि दुर्भाग्यवश हमने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को अपनाते समय योग और आयुर्वेद जैसी प्राचीन पद्धतियों को भुला दिया। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हजारों वर्षो से चली आ रही इन पारंपरिक एवं प्रभावी चिकित्सा पद्धतियों को हम केवल एक वैकल्पिक पद्धति के रूप में देखने लगे। लेकिन, अब इन्हें प्रोत्साहित करने तथा आधुनिक चिकित्सा के साथ इनके समावेश की दिशा में सराहनीय कार्य हो रहा है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि आज के दौर में चिकित्सा सेवाओं में 'पैथी सेंट्रिक' के बजाय 'पेशेंट सेंट्रिक' यानि रोगी केंद्रित दृष्टिकोण रखना चाहिए। इससे लोगों को बेहतरीन एवं प्रभावी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के आपसी समन्वय और समग्र स्वास्थ्य की दिशा में आरोग्य भारती संस्था बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि 'एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य तंत्र' विषय पर परिसंवाद जैसे आयोजन के बहुत ही अच्छे परिणाम निकलेंगे तथा आने वाले समय में देश में एक बेहतरीन स्वास्थ्य नीति तैयार करने में ये काफी सहायक सिद्ध होंगे।

लम्पी चमड़ी रोग की रोकथाम व जागरूकता के लिए विभिन्न स्तरों पर सशक्त प्रयास

शिमला/शैल। पशु पालन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में गौवंश में फैल रहे लम्पी चमड़ी रोग के बारे में पशुपालकों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से समाचार पत्रों, जागरूकता शिविरों, पोस्टर तथा पैम्पलेट्स व अन्य माध्यमों द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी तक 650 शिविरों का आयोजन कर 27,500 किसानों को इस बीमारी के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा स्थिति पर पूर्ण रूप से नजर रखी जा रही है तथा विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकें निरंतर आयोजित की जा रही हैं। सभी प्रभावित जिलों में विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की टीमें बनाई गई हैं, जो रोगी पशुओं को तुरन्त उपचार उपलब्ध करवा रही हैं। प्रत्येक जिला के सहायक निदेशक, परियोजना को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। निदेशालय स्तर पर भी टास्क फोर्स और वार रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर: 0177 – 2650938 है।

उन्होंने कहा कि 22 सितम्बर, 2022 तक प्रदेश के नौ जिलों में 87,645 पशु इस रोग से ग्रसित पाए गए हैं। 5019 गौवंश की मृत्यु दर्ज की गई है तथा अब तक 45,425 पशु इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अभी तक इस रोग की संक्रमण दर 3.65 प्रतिशत तथा मृत्यु दर 5 प्रतिशत के करीब है। प्रदेश में इस बीमारी के लिए संवेदनशील पशुओं की कुल संख्या 24,00,638 है।

इस बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में रोग प्रतिरोधी टीकाकरण किया जा रहा है तथा अब तक 2,37,748 गायों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। सभी जिलों में रोगी पशुओं के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के सभी जिला अधिकारियों को लम्पी चमड़ी रोग के ईलाज, टीकाकरण व रोकथाम इत्यादि के बारे में सम्बन्धित उपायुक्तों से भी निरंतर सम्पर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए है। स्थानीय निकायों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर मक्खी – मच्छर की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सभी जिलों से इस रोग के बारे में प्रतिदिन सूचना एकत्रित कर भारत सरकार को भेजी जा रही है। बीमारी से सम्बन्धित टीकाकरण, मृत्यु व संक्रमण दर इत्यादि से सम्बन्धित विवरण विभाग की वैबसाइट पर बनाए गए डैश बोर्ड पर भी प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा 18 अगस्त, 2022 को पूरे प्रदेश में लम्पी चमड़ी रोग की अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के फलस्वरूप सभी जिलों के उपायुक्तों को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है। पशुओं के आवागमन पर भी रोक लगाई गई है।

राज्य आपदा प्रबन्धान प्राधिकरण द्वारा भी इस बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए मामला केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया गया है ताकि मृत पशुओं के मालिकों को मुआवजा दिया जा सके।

प्रदेश में बीमारी का जायजा लेने के लिए केन्द्र सरकार की टीम ने 12 सितम्बर को जिला बिलासपुर तथा 13 सितम्बर को जिला ऊना का दौरा किया था। इस टीम ने लम्पी चमड़ी रोग के नियंत्रण के लिए पशु पालन विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

प्रदेश में लम्पी चमड़ी रोग समाप्त होने तक विभाग के सभी तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों तबादलों पर रोक लगाई गई है।

गौवंश में फैल रहा लम्पी चमड़ी रोग संक्रामक रोग है। यह विषाणु जनित रोग संक्रमित पशु के सम्पर्क में आने व मक्खी व मच्छर द्वारा संक्रमित पशु को काटने के बाद स्वस्थ पशु को काटने से फैलता है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

हाटी विकास मंच शिमला इकाई के प्रतिनिधिमण्डल ने की राज्यपाल से भेंट

शिमला/शैल। केन्द्रीय हाटी समिति के हाटी विकास मंच शिमला इकाई के एक प्रतिनिधिमण्डल ने राजभवन में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से शिष्टाचार भेंट की।

राज्यपाल ने हाटी समुदाय को

उनकी मांग के अनुरूप जनजातीय दर्जा प्राप्त करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उनके शान्तिपूर्ण आन्दोलन की जीत है। उन्होंने कहा कि यह सभी के साझा प्रयासो और प्रधानमंत्री व केन्द्रीय गृह मंत्री के सहयोग से सम्भव हो पाया है। राज्यपाल ने उनके गिरी पार क्षेत्र का दौरा करने के निमंत्रण को भी स्वीकार किया।

मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा और महासचिव अतर तोमर ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने पर बधाई के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अधिकार लम्बे संघर्ष के बाद मिला है, जिसके लिए पूरा समुदाय आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति से यह निर्णय सम्भव हो पाया। इस निर्णय से आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित होंगी।

हाटी विकास मंच ने राज्यपाल को पारम्परिक डांगरा और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर मंच के मुख्य प्रवक्ता डॉ. रमेश सिंगटा, अध्यक्ष एम.आर शर्मा, सचिव सुरेश सिंगटा, उपाध्यक्ष मदन तोमर सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित थे।

एचआरटीसी खरीदेगा 350 साधारण और 22 ए.सी. सुपर लैग्जरी बसें

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की वाहन क्रय समिति की बैठक आयोजित हुई। परिवहन मंत्री ने बताया कि बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए 350 (बीएस – 6) साधारण बसें क्रय करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। इसमें 28 सीट क्षमता की 25 बसें, 36 सीट क्षमता की 150 बसें तथा 46 सीट क्षमता की 175 बसें सम्मिलित हैं।

उन्होंने बताया कि बैठक में 39 सीट क्षमता की 22 वातानुकूलित सुपर लैग्जरी बसें खरीदने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई।

बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को गुणात्मक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निरंतर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन बसों की खरीद से राज्य के सभी क्षेत्रों विशेषकर दूर – दराज के क्षेत्रों में लोगों को बस सेवा प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

बैठक में एचआरटीसी के प्रबन्ध निदेशक सन्दीप कुमार, समिति के सदस्य सुशील शर्मा, रतन सिंह राठौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्वतंत्रता संग्राम व विकास में हिमाचल ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका: नरेन्द्र मोदी

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से मण्डी के ऐतिहासिक पद्ढल मैदान में प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विशाल युवा विजय संकल्प रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र की गठबन्धन सरकारें लोगों को विकास प्रदान करने में विफल रही जिससे विश्व में भारत की क्षमता पर संशय पैदा हुआ। इसलिए निर्बाध विकास के लिए स्थिरता समय की मांग है। प्रधानमंत्री को खराब मौसम के कारण मण्डी का दौरा रद्द करना पड़ा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं के आत्मविश्वास और कुशलता से भारत को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार प्रदेश के युवाओं को देश के विकास में भागीदार बनने के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। देश के विकास और सुरक्षा में हिमाचल प्रदेश के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास और स्वतंत्रता संग्राम में इस पहाड़ी प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के विकास में हिमाचल प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा का निरंतर उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वासन दिया कि प्रदेश के लोगों का आर्शीवाद और स्नेह प्राप्त करने के लिए आगामी दिनों में वह प्रदेश का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए रिकॉर्ड धन राशि आवंटित की है और प्रदेश के सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में स्थान प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले आठ वर्षो के दौरान हिमाचल प्रदेश को विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग फार्मा पार्क और मेडिकल उपकरण पार्क युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव और रिश्ता है। वह जब भी प्रदेश का दौरा करते हैं, उन्हें अपने दूसरे घर में आने की भावना का अहसास होता है। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही आगामी दिनों में प्रदेश का दौरा करेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए यह गौरव का क्षण होता कि छोटी काशी मण्डी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत किया जाता, लेकिन खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से मण्डी नहीं आ सके।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार का प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पार्क प्रदेश के लोगों के लिए कई मायनों में लाभदायी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है और लगभग 30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 1000 करोड़ रुपये है, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश के उन तीन राज्यों में से एक है जिन्हें बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए चयनित किया गया है। यह प्रदेश के प्रति प्रधानमंत्री के स्नेह को दर्शाता है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री का स्नेह प्राप्त है। प्रधानमंत्री प्रदेश की विकासात्मक आवश्यकताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। प्रदेश की जनता का भी प्रधानमंत्री के साथ विशेष लगाव है, जो राज्य की सबसे बड़ी सम्पति है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क स्वीकृत किया गया है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा प्रदान करने के साथ हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगा।

इस अवसर पर सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी अपने विचार साझा किए और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रदेश के युवाओं का आभार व्यक्त किया।

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पहाड़ी युवाओं में समाज में गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाने की क्षमता है।

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शिमला शहर के लिए 713 करोड़ रुपए स्वीकृत:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला शहर के विकासनगर में लगभग तीन करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहले चरण में निर्मित लिफ्ट और फुट ओवर ब्रिज का शुभारंभ किया।

पुलिस चौकी विकासनगर के पास बनी 36 मीटर ऊंची यह लिफ्ट लोगों को सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंचाएगी। इस लिफ्ट में 20 लोग एक साथ आ-जा सकेंगे और उन्हें चढ़ाई से भी छुटकारा मिलेगा। वहीं खलीणी-पंथाघाटी सड़क पर विकासनगर के 53 मीटर लंबे फुट ओवर ब्रिज से लोगों को बिना किसी दुर्घटना के खतरे से सड़क पार करने में आसानी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकासनगर में लिफ्ट बनने से स्थानीय निवासियों, नौकरी पेशा लोगों और स्कूली बच्चों को सबसे अधिक लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना रोपवेज़ एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरटीडीसी) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। प्रथम चरण के कार्य के उपरांत अब दूसरे चरण में 24 मीटर तथा तीसरे चरण में 29 मीटर ऊंची लिफ्ट और 44 मीटर व 47 मीटर लंबे फुट ओवर ब्रिज से विकासनगर को ब्रॉकहर्स्ट से जोड़ा जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 7.62 करोड़ रुपए है। यह कार्य आगामी जून माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इससे विकासनगर से ब्रॉकहर्स्ट तक लोगों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा और वहां से छोटा शिमला तक 12.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पैदल वॉक-वे परियोजना का कार्य भी जारी है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर लोगों को विकासनगर से छोटा शिमला तक सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर के लिए 713 करोड़ रुपए की 216 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर में स्मार्ट पार्किंग, फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर, गरीबों के लिए पक्के घर, कारोबारियों के लिए नई दुकानें, तहबाजारियों के लिए नए स्टॉल की सुविधा प्रदान की जा रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि फुट ओवरब्रिज के निर्माण से संबंधित 91.19 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जो शहर में पैदल चलने वालों के लिए यातायात में सुरक्षा को बढ़ावा देंगी। शहर में निगरानी व आईटी से संबंधित करीब 45 करोड़ रुपए की चार परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इससे महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं की प्रभावी निगरानी के लिए आईसीटी बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट बस स्टॉप व सब-वे के निर्माण व ई-मोबिलिटी से संबंधित 39.15 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर विभिन्न स्तरों पर कार्य जारी है और शीघ्र ही शिमला शहर एक नए स्वरूप में नज़र आएगा।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, उपायुक्त आदित्य नेगी, नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली, स्थानीय जनप्रतिनिधि, आरटीडीसी के निदेशक अजय शर्मा, भाजपा पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के विक्रेताओं पर कड़ी कारवाई

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त युनूस ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध शराब के विक्रेताओं पर कड़ी कारवाई कर नकली होलोग्राम, लेबल व कॉर्क ज़ब्त कर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत जिला शिमला में गुप्त सूचना के आधार पर शनान स्थित परिसर का विभाग की गठित टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान परिसर में 21 बोतलें अंग्रेजी शराब (फॉर सेल इन चण्डीगढ़) एवं बियर की 2 बोतलें पाई गई। परिसर में 16230 नकली होलोग्राम एवं 11984 नकली लेबल भी पाये गये। इसके अतिरिक्त एक बोरी में देसी शराब के नकली ढक्कन को भी कब्ज़े में लिया गया। उन्होंने कहा कि एक गैलन 50 किलो ग्राम के संदिग्ध पदार्थ को कब्जे में लेकर उसे पुष्टि के लिए रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।

उन्होंने बताया कि दोषियों के विरुद्ध ढली थाना में अवैध शराब, नकली होलोग्राम एवं नक़ली लेबल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त विभाग की अन्य टीम द्वारा शिमला में एक ढाबे से 7 बोतल अवैध शराब कब्ज़े में लेकर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई गई।

युनूस ने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कारवाई अमल में लाई गई है जिसमें कुल्लू, नूरपुर, सिरमौर में अधिकारियों द्वारा 3605 लीटर कच्ची शराब (लाहन) कब्ज़े में लेकर नियमानुसार नष्ट किया गया है। इसके अलावा विभागीय टीमों द्वारा प्रदेश में अंग्रेजी शराब की 63 बोतलें, 167 बोतलें देसी शराब, 34 बोतलें बियर एवं 96 बोतलें वाइन आबकारी अधिनियम के अंतर्गत ज़ब्त की हैं।

आबकारी आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर 65 विशेष टास्क फ़ोर्स का गठन किया है। मदिरा एवं मादक पदार्थों, अन्य प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के परिवहन पर नजर रखने के लिए मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। टास्क फ़ोर्स को प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री, निर्माण एवं तस्करी को रोकने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। विभाग द्वारा मदिरा निर्माण, थोक विक्रेता वाली सभी इकाइयों में अवैध रूप से मदिरा परिवहन पर रोक लगाने के दृष्टिगत आई.पी. बेस्ड सी.सी.टी.वी. कैमरा से निगरानी की जा रही है।

हि.प्र. राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उत्पादों की बिक्री बढ़ी

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के निदेशक मण्डल की 189वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि निगम के उत्पादों की बिक्री में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जुलाई माह के मुकाबले वित्त वर्ष 2022-23 में इसी अवधि के दौरान निगम के उत्पादों की बिक्री में 130 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक निगम ने 595.69 लाख रुपये मूल्य के उत्पाद विक्रय किए थे, जबकि इस वित्त वर्ष में इसी अवधि के दौरान 777.14 लाख रुपये मूल्य के उत्पाद विक्रय किए गए हैं।

बिक्रम सिंह ने कहा कि निगम के उत्पादों की गुणवता और विपणन तकनीक में निरंतर सृजनात्मकता व सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा 63 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 780 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल इम्पोरियम शिमला के जीर्णोद्धार के उपरान्त इसमें उत्पादों की बिक्री और ग्राहकों की संख्या में भी आशातीत बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

बैठक में उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम की प्रबन्ध निदेशक कुमुद सिंह ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। इस अवसर पर निगम के निदेशक बलदेव सिंह, महाप्रबन्धक योगेश गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हि.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से 9766 लोगों को मिला रोजगार

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2018 से 2022 तक 9766 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। यह जानकारी उन्होंने बोर्ड की 238वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इस अवधि के दौरान बोर्ड के माध्यम से 1566 औद्योगिक इकाइयां को सहायता प्रदान की गई।

उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 104.34 प्रतिशत वित्तीय तथा 101.15 प्रतिशत भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 15 सितम्बर तक 16.82 लाख रुपये मार्जिन राशि के 454 आवेदन विभिन्न बैंकों को प्रायोजित किए गए हैं।

बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

बैठक की कार्यवाही का संचालन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत भारद्वाज ने किया। बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य सागर दत्त भारद्वाज, निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति, विशेष सचिव किरण भड़ाना, राज्य नोडल अधिकारी संजीव जस्टा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हमें ऐसी शिक्षा चाहिए,जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बड़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्यों बना है नफरती ब्यानों का वातावरण

नफरती ब्यानों से हुई वस्तुस्थिति पर उभरी चिन्ताओं पर चिन्तन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस के.एम.जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश राय की खण्डपीठ के पास सुदर्शन टीवी द्वारा दिखाये यूपीएससी जिहाद शो और धर्म संसदों में दिये गये ब्यानों तथा कोविड महामारी के दौरान एक समुदाय विशेष को चिन्हित व इंगित करते हुए सोशल मीडिया के मंचों पर आयी टिप्पणियों पर आयी याचिकाएं निपटारे के लिये लगी हैं। शीर्ष न्यायालय ने इस पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए यह प्रश्न उठाया है कि आखिर देश जा कहां जा रहा है? अदालत ने इस पर सरकार की मुकदर्शिता पर भी चिन्ता व्यक्त करते हुये इस संदर्भ में एक सख्त नियामक तंत्र गठित किये जाने पर आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार से इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय में उठे सवालों में ही कमीशन की सिफारिश और चुनाव आयोग के सुझाव भी चर्चा में आये हैं। यह भी सामने आया है कि कानून में नफरती ब्यान और अफवाह तक परिभाषित नहीं है। देश के 29 राज्यों में से केवल 14 ने ही इस पर अपने विचार रखे हैं यह सामने आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को अपनी राय शीर्ष अदालत में रखने के निर्देश दिये हैं। शीर्ष अदालत में यह सब घटने के बाद कुछ टीवी चैनलों ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस भी आयोजित की है। इस सारे मन्थन से क्या निकल कर सामने आता है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आज देश में इस तरह का वातावरण क्यों निर्मित हुआ है? केन्द्र में सत्तारूढ़ पक्ष इस पर क्यों मौन चल रहा है? उसे इससे किस तरह का राजनीतिक लाभ मिल रहा है? इस मन्थन से इन सवालों का कोई सीधा संद्धर्भ नहीं उठाया जा रहा है। जबकि मेरा मानना है कि यह सवाल इस बहस का केन्द्र बिन्दु होने चाहिये। अदालत ने भी सरकार की खामोशी पर सवाल उठाते हुए एक सख्त नियामक तन्त्र के गठन की बात की है। आज केन्द्र में वह राजनीतिक दल सत्तारूढ़ है जिसका वैचारिक नियन्त्रण आर.एस.एस. के पास है। 1947 में देश की आजादी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने वैचारिक धरातल को विस्तार देने के लिये 1948 और 1949 में ही युवा संगठन के नाम पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन करने के साथ ही हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी का गठन कर लिया। यह वह क्रियात्मक कदम थे जिन से आने वाले वक्त में मीडिया यूथ की भूमिका का आकलन उसी समय कर लिया गया। उसके बाद आगे चलकर इसकी अनुषांगिक इकाइयों संस्कार भारती और इतिहास लेखन प्रकोष्ठ आदि का गठन इस दिशा के दूसरे मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। इसी सबका परिणाम संघ के सनातकों के रूप में सामने आया। मजे की बात तो यह है कि यह स्नातक लाखों की संख्या में तृतीय वर्ष पास करके आ चुके हैं। अधिकांश राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों में शामिल हो चुके हैं लेकिन इस पाठयक्रम को लेकर चर्चा नहीं के बराबर रही है। आज के नये राजनीतिक कार्यकर्ताओं से चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हो यदि यह पूछा जाये कि संघ का आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक चिन्तन क्या है तो वह शायद कुछ भी न बता पायें। उनकी नजर में यह एक सांस्कृतिक संगठन है जिसकी सांस्कृतिक विरासत मनुस्मृति से आगे नहीं बढ़ती। इसी संस्कृति का परिणाम है कि आज समाज का एक बड़ा वर्ग न्यायपालिका से लेकर राजनेताओं तक हिन्दू राष्ट्र के एजेंडे में शामिल हो चुका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 1998 के राष्ट्रीय अधिवेशन में त्रीस्तरीय संसद के गठन का प्रस्ताव पारित होने के बाद आज हालात इन ब्यानों तक पहुंच गये हैं। स्कूलों में मनुस्मृति को पाठयक्रम का हिस्सा बनाने की बात हो रही है। क्योंकि जब गुजरात दीन्नानाथ बत्रा की किताबों को स्कूल पाठयक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा था तब इसकी चर्चा तक नहीं उठाई गयी थी। आज संघ की विचारधारा पर जब तक सार्वजनिक बहस के माध्यम से स्वीकार्यता य अस्वीकार्यता तक नहीं पहुंचा जाता है तब तक हिन्दू राष्ट्र के एजेंडे की वकालत के लिए ऐसे नफरती ब्यानों को रोकना आसान नहीं होगा।

सावधान! पाकिस्तान की तरह भारत में आकार ले रहा है बरेलवी कट्टर मुसलमानों की जमात

गौतम चौधरी

दावत-ए-इस्लामी (डीईआई), एक पाकिस्तानी बरेलवी सुन्नी मुसलमानों का एक समूह है। इसी समूह के प्रभावित दो युवाओं ने अभी हाल ही में उदयपुर में एक हिन्दू दर्जी की हत्या कर दी। उक्त दर्जी पर कथित तौर पर आरोप लगाया गया कि उसने भाजपा की निष्कासित नेत्री नूपुर शर्मा वाले मामले में एक तथ्य को अपने सोशल मीडिया वाले पेज पर साझा किया था। हालांकि बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उस दर्जी को सोशल मीडिया से कोई लेना-देना नहीं था और उसके बेटे ने भावनावश ऐसा किया था। परंतु इस्लाम के चरमपंथ में विश्वास करने वाले दो युवकों ने दर्जी की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी।

हत्या में शामिल व्यक्तियों और (डीईआइ) के बीच संबंध सामने आने के बाद भारत की जांच एजेंसिया सकते में है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए उदयपुर मामले के आरोपी डीईआई के संस्थापक मौलाना इलियास अत्तर कादरी के नाम पर अपने नाम में अटारी शीर्षक का प्रयोग करते हैं। जिस मौलाना से प्रेरित होकर हत्यारों ने हत्या को अंजाम दिया वह हत्यारों की प्रेरणा के स्रोत पर कई सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान में देवबंदी समूहों के बढ़ते प्रभाव के सामने बरेलवाद को मजबूत करने के प्रयास के रूप में 1981 में पाकिस्तान में मुहम्मद लयस अत्तर कादरी द्वारा डीईआई की स्थापना की गई थी। इस संगठन के बारे में थोड़ी जानकारी जरूरी है। ईशनिंदा के आरोप में पाकिस्तान के गवर्नर पंजाब, सलमान तासीर का अपने अंगरक्षक मुमताज कादरी द्वारा हत्या के बाद डीईआई का नाम चर्चा में आया था। इसके बाद डीईआई के साथ मुमताज कादरी के गहरे जुड़ार का खुलासा तब हुआ जब डीईआई की राजनीतिक साखा तहरीक-ए-लब्बैक (टीआईपी) ने कादरी को मुक्त करने के लिए पूरे पाकिस्तान में धरना और प्रदर्शन आयोजित करने लगा। उस समय तो उस आन्दोलन को दबा दिया गया लेकिन बाद में इमरान सरकार को तहरीक-ए-लब्बैक के सामने घुटने टेकने पड़े। कादरी को फांसी दिए जाने के बाद अन्याय के नारे से टीएलपी तेजी से बढ़ने लगा। टीएलपी के कट्टरपंथी उदाहरण ने सुनिश्चित किया कि बरेलवाद हिंसा का पर्याय है। यही नहीं यह भी साबित किया कि इस संगठन में सूफी घटक अब काफी कमजोर पर चूका हैं। इधर भारत में भी पाकिस्तान के तर्ज पर संगठन खड़ा करने की कोशिश हुई है। 1992 में डीईआई का भारतीय मॉयूल खड़ा किया गया। मुंबई में मोहम्मद शाकिर एएच नूरी ने सुन्नी बरेलवियों का एक संगठन खड़ा किया और उसका नाम दावत-ए-इस्लामी रखा। उदयपुर की घटना की भारत के लगभग सभी प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने निंदा की लेकिन नूरी के संगठन का आधिकारिक निंदा आना बाकी है। यह साबित करता है कि पाकिस्तान की तरह, भारत में भी कट्टर बरेलवियों का एक संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करने की फिराक में है।

उदयपुर की हत्या ने यह साबित कर दिया है कि वैचारिक रूप से प्रेरित और पथभ्रष्ट व्यक्ति अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह तब्लीगी जमात (टीजे) नामक कट्टर मुसलमानों की टोली की तरह ही काम करता है। टीजे के बारे में कई बातें हम समझ चुके हैं लेकिन डीईआई के बारे में आम भारतीयों का ज्ञान अभी कम है। डीईआई भले बरेलवियों का संगठन हो लेकिन अब इस संगठन में सूफीवादी तत्व अब बेहद कमजोर हो चुके हैं। यह भी दुनिया के अन्य कट्टरपंथी मुसलमान संगठनों की तर्ज पर आम मुसलमानों को मिलिटराई कर रहा है।

भारत में टीजे यानी तब्लीगी जमात के कई कारनामें सामने आए हैं। वैसे तो टीजे अपने आप को आध्यात्मिक सुधारवादी आन्दोलन बताता है लेकिन सलमान तासीर की हत्या के बाद जिस प्रकार पाकिस्तान में डीईआई का कट्टरपंथी चेहरा उजागर हुआ उसी प्रकार 9/11 के हमलों के बाद टीजे का कट्टरपंथी चेहरा भारत में सामने आया। लस्कर-ए-झांगवी के साथ टीजे का जुड़ाव जगजाहिर है। भारत में टीजे और पाकिस्तान में डीईआई का जुड़ाव भी अब सामने आने लगा है। भारत में काम करने वाला कट्टर सुन्नी मुसलमानों का समूह लब्लीगी जमात अपनी अंतरराष्ट्रीय पहुंच और दुनिया के अन्य देशों में बड़ी संख्या में आनुयायियों के कारण डीईआई से आगे निकल चुका है। जिस प्रकार डीईआई ने अफगान-सोवियत युद्ध में भाग नहीं लिया, उसी प्रकार टीजे से जुड़े पाकिस्तानियों ने भी ऐसा ही किया था। टीजे के संबद्ध समूह जैसे-लश्कर-ए -झांगवी, सिपाह-ए-सहाबा और तालिबान को भी पाकिस्तान और कश्मीर में हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के लिए जाना जाता है।

पाकिस्तानी सुन्नी तहरीक ने इन दिनों कई नारे गढ़े हैं। मसलन, ''जवानियां लुटायेंगे मस्जिदन बचायेंगे'', ''तौहीन रसलत की एक ही साजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा'' आदि नारे तहरीक की जमात में बेहद फेमस हो रहा है। डीईआई के बढ़ते खतरे को पाकिस्तान ने सलमान तासीर की हत्या के बाद भी नजरअंदाज किया और अब संगठन इस हद तक बढ़ गया है कि इसके नेताओं पर इस्लामाबाद द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद इसके अनुयायियों ने इस्लामाबाद पर कब्जा करके पाकिस्तानी सरकार को प्रतिबंध वापस लेने के लिए मजबूर तक कर दिया। मतलब साफ है, अब पाकिस्तान की इस्लामिक सरकार भी इस तहरीक के सामने घुटने टेक चुकी है। भारत, यदि उसी गलती को दुहराता है और बरेलवी जानकर इस संगठन को छूट दी जाती है तो फिर भारत का भी वही हश्र होगा जो इन दिनों पाकिस्तान का हो रहा है। उदयपुर की घटना ने देश को रास्ता दिखाया है। भारत में डीईआई जैसा एक बेहद खतरनाक मॉयूल आकार ले रहा है। इसके प्रति सहानुभूति रखने वालों की पहचान की जानी चाहिए और युवाओं के कट्टरपंथ को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, वैचारिक रूप से प्रेरित संगठनों जैसे-टीजे, तहफ्फुज-ए- नमूस-ए-रिस्लाट आदि पर भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को नजर रखनी चाहिए, ताकि कट्टरता की किसी भी घटना को जड़ से खत्म किया जा सके।

मुख्यमंत्री एक बीघा योजना महिलाओं के जीवन में लाई खुशहाली

शिमला। महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है। महिलाओं के विकास के बिना समाज के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। महिलाओं का सामाजिक -आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। महिलाएं इन योजनाओं का बढ़-चढ़ कर लाभ उठा रही है। इन योजनाओं के फलस्वरूप महिला सशक्तिकरण में हिमाचल देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरा है।

ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनकी आर्थिकी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एक बीघा योजना शुरू की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन का अनुसरण कर ग्रामीणों को किचन गार्डनिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किचन गार्डन को विकसित कर पोषणयुक्त सब्जियों और फलों का उत्पादन कर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ उत्पादित उत्पादों को खुले बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित कर रही है।

मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तहत प्रदेश में भूमि सुधार, नर्सरी उत्पादन, फलदार वृक्षारोपण, केंचुआ खाद गड्ढा निर्माण, अजोला पिट निर्माण, सिंचाई और जल संचयन संरचना निर्माण और गौशाला निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत अब तक 17292 लोगों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में अब तक इस योजना के तहत 41 करोड़ 87 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। बिलासपुर जिला में 309 लोगों को 37.34 लाख रुपये, चम्बा जिला में 355 लोगों को 118.43 लाख रुपये, हमीरपुर जिला में 928 लोगों को 146.37 लाख रुपये, कांगड़ा जिला में 1792 लोगों को 304. 10 लाख रुपये, किन्नौर जिला में 41 लोगों को 4.44 लाख रुपये, कुल्लू जिला में 1,123 लोगों को 114.21 लाख रुपये, लाहौल-स्पीति जिला में 5 लोगों को 3. 68 लाख रुपये, मण्डी जिला में 3,124 लोगों को 882.44 लाख रुपये, शिमला जिला में 5,856 लोगों को 1452.09 लाख रुपये, सिरमौर जिला में 2,066 लोगों को 830.21 लाख रुपये, सोलन जिला में 1218 लोगों को 181.93 लाख रुपये और ऊना जिला में 475 लोगों को 112.25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना का लाभ उठाकर महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। जिला ऊना के हरोली खण्ड की ग्राम पंचायत लोअर पंजावर के स्वयं सहायता समूह पीहू की सुदेश कुमारी इस योजना के माध्यम से प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा प्रदान कर रही है। उन्होंने वर्ष 2019 में इस योजना के लिए आवेदन किया था। उन्हें इस योजना के अन्तर्गत 83 हजार 740 रुपये की सहायता राशि स्वीकृत हुई। इस राशि का उपयोग कर उन्होंने आम के 18 पौधे लगाए और उनकी बाड़बंदी भी की। इसके अतिरिक्त उन्होंने किचन गार्डन मॉडल का उपयोग करके प्राकृतिक खेती से लौकी, कद्दू इत्यादि सब्जियां भी उगाई। उनका कहना है कि वह खेती में गोबर की खाद और नीम अस्त्र जैसे पारंपरिक तौर तरीकों का उपयोग करती हैं। उनके उत्पाद जहरीले रसायनों से भी बच रहे हैं और खेती की लागत में भी कमी आई है। मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री एक बीघा जमीन से उन्होंने खेती को विस्तार प्रदान किया है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से बढ़ती उत्पादकता को देखकर अन्य महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हो रही है। सुदेश जैसे कई उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में खुशहाली आ रही है।

शांतिप्रिय भारत को युद्ध से डरने वाला समझने की गलती नहीं करनी चाहिए:राजनाथ सिंह

शिमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले हिमाचल प्रदेश के सशस्त्र बलों के वीर जवानों के परिवारों को सम्मानित किया। हिमाचल के कांगड़ा जिले के बाडोली में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री ने पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा (1947), ब्रिगेडियर शेर जंग थापा, महावीर चक्र (1948), लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, परमवीर चक्र (1962), कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र (1999) और सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र (1999) सहित उन सभी युद्ध नायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिनका नाम उनकी बेजोड़ बहादुरी और बलिदान के लिए हर भारतीय के दिलों में अंकित है।

राजनाथ सिंह ने युद्ध वीरों के परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि देश वीर जवानों द्वारा दिए गए बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल हमेशा लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे, क्योंकि उनमें अनुशासन, कर्तव्य के प्रति समर्पण, देशभक्ति और बलिदान के गुण हैं और वे राष्ट्रीय गौरव और विश्वास के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि पृष्ठभूमि, धर्म और पंथ मायने नहीं रखते, बल्कि यह मायने रखता है कि हमारा प्रिय तिरंगा ऊंचा उड़ता रहे।

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है और इसकी बहादुरी के लिए दुनिया भर में इसकी सेना का सम्मान किया जाता है। उन्होंने यह कहते हुए कि भारत ने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया है, न ही उसने एक इंच भी विदेशी भूमि पर कब्जा किया है, राष्ट्र को आश्वासन दिया कि यदि भारत में सद्भाव को बिगाड़ने का कोई प्रयास किया गया, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन इसे कायर या युद्ध से डरने वाला समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में जब हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर कोविड-19 से निपट रहे थे, हमें चीन के साथ उत्तरी सीमा पर तनाव का सामना करना पड़ा। गलवान घटना के दौरान हमारे जवानों के साहस ने यह साबित कर दिया कि सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भारत कभी नहीं झुकेगा।

2016 सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट हवाई हमले पर, राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई रणनीति ने उन लोगों की कमर तोड़ दी है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक सुविचारित नीति के तहत पाकिस्तान में सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियाँ की गईं। उरी और पुलवामा हमलों के बाद, हमारी सरकार और सशस्त्र बलों ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट हवाई हमले के माध्यम से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। हमने दिखाया कि हमारे बलों के पास इस तरफ और जरूरत पड़ने पर सीमा के दूसरी तरफ भी कारवाई करने की क्षमता है। भारत की छवि में बदलाव आया है। अब इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गंभीरता से सुना जाता है।

रक्षा मंत्री ने देश को मजबूत और 'आत्मनिर्भर' बनाने के सरकार के अटूट संकल्प और प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किए गए उपायों के कारण हासिल प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पहले भारत को एक रक्षा आयातक के रूप में जाना जाता था। आज, यह दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातकों में से एक है। आठ साल पहले लगभग 900 करोड़ रुपये से रक्षा निर्यात बढ़कर 13,000 करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया है। हमें उम्मीद है कि 2025 तक रक्षा निर्यात 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा और 2047 के लिए निर्धारित 2. 7 लाख करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।

राजनाथ सिंह ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन और सैन्य मामलों के विभाग की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए किए गए कुछ प्रमुख सुधार हैं। 'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के दरवाजे लड़कियों के लिए भी खोल दिए गए हैं, सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जा रहा है। हमने युद्ध पोतों पर महिलाओं की तैनाती का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक 'नए भारत' का निर्माण कर रही है जो हमारे सभी शांतिप्रिय मित्र देशों को सुरक्षा और विश्वास की भावना प्रदान करेगा। तथा गलत इरादे वाले लोगों को धूल के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा।

रक्षा मंत्री का विचार था कि सशस्त्र बलों के नायकों से ली गई प्रेरणा ही भारत के विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ने का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि जब युद्ध के काले बादल दिखाई देते हैं और राष्ट्रीय हितों पर हमला होता है, तो यह सैनिक ही होता है जो उस हमले को सहन करता है और देश की रक्षा करता है। यह शहीद हुए नायकों का सर्वोच्च बलिदान ही है जो लोगों को जीवित रखता है।

राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश को भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना हर सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ-साथ देश की खुफिया और संचार क्षमता को प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि सीमावतह क्षेत्रें में सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बनी अटल सुरंग ऐसी ही बड़ी परियोजनाओं में से एक है।

रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों को देश की संपत्ति बताते हुए कहा कि मातृभूमि की सेवा में उनके बलिदान की कोई कीमत तय नहीं की जा सकती। उन्होंने पूर्व सैनिकों की भलाई और कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और कर्तव्य को दोहराया। उन्होंने 'डिजिटल इंडिया' के तहत ऑनलाइन सेवाओं सहित रक्षा मंत्रालय द्वारा उनके जीवनयापन को आसान बनाने के लिए उठाए गए उन कदमों को सूचीबद्ध किया, जिनमें स्मार्ट कैंटीन कार्ड, भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र केन्द्रीय सैनिक बोर्ड और पुनर्वास सेवा महानिदेशालय तक ऑनलाइन पहुंच और पेंशन प्रशासन प्रणाली (रक्षा) (स्पर्श) पहल के लिए प्रणाली की शुरुआत शामिल हैं।

राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इसे इतिहास में किसी भी प्रकार की संपत्ति, अधिकार या शक्ति के बजाय मानवता के लिए लड़े गए युद्ध के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जनरल जैकब, जनरल सुजान सिंह उबान और जनरल ऑफिसर इन कमांड एयर मार्शल लतीफ के नाम, जिन्होंने भारत को शानदार जीत दिलाई, कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। युद्ध में भारतीय सैनिकों में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख और यहूदी शामिल थे। यह सर्वधर्म समभाव (सभी धर्मों के लिए सम्मान) के प्रति भारत के विश्वास का प्रमाण है। ये सभी वीर सैनिक अलग-अलग मातृभाषा वाले अलग-अलग राज्यों के थे, लेकिन वे भारतीयता के एक मजबूत और साझा धागे से बंधे हुए थे।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने हिमाचल प्रदेश में 1,032 हेक्टेयर में अवैध भांग (गांजा) की खेती को नष्ट किया

शिमला। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश में दो सप्ताह तक चले नशीले पदार्थो को नष्ट करने के सबसे बड़े अभियानों में से एक के दौरान 1032 हेक्टेयर (12,900 बीघा) में अवैध भांग (गांजा) की खेती को नष्ट कर दिया।

हिमाचल प्रदेश में अवैध भांग (गांजा) की खेती के बारे में ठोस खुफिया जानकारी मिलने पर सीबीएन के अधिकारियों की कई टीमें गठित की गई और उन टीमों को रवाना किया गया। सीबीएन के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी का सत्यापन किया और उसके बाद भौतिक सर्वेक्षण किए जिसके परिणामस्वरूप और अधिक दायरे में फैली अवैध खेती का पता चला। इसके बाद जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस के सहयोग से इस अवैध खेती को नष्ट करने का अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के दौरान, सीबीएन के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने के साथ-साथ ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने की दोतरफा रणनीति अपनायी गई।

शरीर और मन पर नशीले पदार्थो के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करके सामुदायिक एकजुटता के तरीके को अपनाया गया। नशीले पदार्थो की वजह से युवाओं और बच्चों के भविष्य पर मंडराने वाले खतरे के बारे में बताया गया। ग्राम प्रधानों और सदस्यों को एनडीपीएस अधिनियम के प्रासंगिक दंड प्रावधानों के बारे में भी समझाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीणों द्वारा गांवों के आसपास अवैध भांग के बागानों को नष्ट करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ग्रामीणों ने सीबीएन अधिकारियों की देखरेख में सक्रिय रूप से इस अभियान में भाग लेकर अवैध खेती को नष्ट करने में सीबीएन के अधिकारियों की सहायता की।

सीबीएन के अधिकारियों की चार टीमों को एक ही साथ कई क्षेत्रों में कारवाई करने का दायित्व दिया गया और उन्हें बड़े दायरे में फैली भांग की अवैध खेती वाले कुछ क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम करने की छूट दी गई। इस अभियान की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस समूची कारवाई के दौरान वन विभाग, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी भी इन टीमों के साथ रहे। यह उल्लेखनीय है कि चूंकि यह सेब और अनार की कटाई का मौसम है, कामगारों की उपलब्धता एक समस्या थी। लेकिन यह बाधा सीबीएन के टीमों के धैर्य और दृढ़ संकल्प को रोकने में विफल रही, जो खड़ी ढलानों और बारिश वाले दुर्गम इलाकों में कार्रवाई में जुट गई और अवैध खेती को नष्ट करने का अभियान चलाया। सीबीएन के अधिकारी रोजाना समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाई की और यहां तक कि संवेदनशील क्षेत्रों में डेरा भी डाला ताकि भांग की अवैध खेती को नष्ट करने के काम में तेजी लाई जा सके। बाद में डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) के अधिकारी भी इस अभियान में शामिल हो गए।

संवेदनशील स्थानों को टैग/चिन्हित करने के लिए जीपीएस निर्देशांक का उपयोग किया गया और ड्रोन का उपयोग अवैध भांग (गांजा) की खेती वाले क्षेत्रों का पता लगाने व निगरानी के लिए किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस पूरे अभियान को काफी सफलता मिली।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के नारकोटिक्स कमिश्नर राजेश एफ. ढाबरे ने कहा, इसी तरह की तत्परता के साथ देश के अन्य हिस्सों में भी मिशन कारवाई जारी रहेगी और सीबीएन नशीली पदार्थो के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

इस पूरे अभियान के दौरान लॉजिस्टिक्स और श्रमशक्ति के मामले में जिला कलेक्टर, सीसीएफ व एसपी कुल्लू और डीआरआई के कार्यालयों द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत नशीले पदार्थो के खिलाफ कानूनों का प्रवर्तन कराने वाली शीर्ष एजेंसी है, जिसे इसकी अन्य जिम्मेदारियों के साथ-साथ भांग और अफीम की अवैध खेती की पहचान करने और उसे नष्ट करने का काम सौंपा गया है।

सीबीएन ने पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड आदि जैसे कई राज्यों में नशीले पदार्थो को नष्ट करने का अभियान चलाया है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षो में अफीम और भांग की 25,000 हेक्टेयर से अधिक की अवैध खेती नष्ट की गई है। सीबीएन ने इस साल फरवरी और मार्च के महीने में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 3,600 हेक्टेयर में लगे अवैध अफीम को नष्ट किया था। सीबीएन भविष्य में भी देश भर में अवैध खेती को नष्ट करने के ऐसे अभियान को जारी रखने का इरादा रखता है।

पर्यटन स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की जाएगी :जी किशन रेड्डी

शिमला। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी की उपस्थिति में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में राज्य पर्यटन मंत्रियों का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। 12 राज्यों मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, मिजोरम, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

जी किशन रेड्डी ने सभी राज्य प्रतिनिधियों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। रेड्डी ने आग्रह किया कि सभी राज्य पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करें और उन्हें अपनाएं। पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्यों को अपने स्तर पर विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों और हितधारकों के साथ इस तरह के सम्मेलन आयोजित करने चाहिए। रेड्डी ने युवा पर्यटन क्लबों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि ये क्लब इस क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं।

रेड्डी ने यह भी जानकारी दी कि पर्यटन स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने राज्यों और हितधारकों से सभी होटलों और पर्यटन स्थलों पर झंडा लगाने की भी अपील की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक दूसरे से सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए समय-समय पर इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और उम्मीद है कि इससे बहुत जल्द वांछित परिणाम मिलेंगे।

सम्मेलन के परिणाम के बारे में बात करते हुए, पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि भारत मुख्य रूप से घरेलू पर्यटन के माध्यम से दुनिया भर के टूरिज्म सेक्टर की रिकवरी में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी प्रमुख पर्यटन सूचकांकों जैसे घरेलू हवाई यात्री ट्रैफिक, होटल में पर्यटकों की मौजूदगी और पर्यटकों की संख्या ने महामारी से पहले के स्तर तक सुधार के संकेत दिखाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा भारत के पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक समग्र दृष्टि और रणनीति के साथ तैयार किया गया है और 2047 में इस क्षेत्र द्वारा 1 लाख करोड़ डालर के स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य है। इसी पृष्ठभूमि में मंत्रालय जिम्मेदार और लंबे समय तक बने रहने वाले पर्यटन स्थलों को विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। भारत सरकार पर्यटन में एमएसएमई का समर्थन करना जारी रखेगी और इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावनाओं का पूरा फायदा उठाना जारी रखेगी। महामारी के कारण पर्यटन अर्थव्यवस्था पर पड़े असर से पूरी तरह से उबरने के लिए पर्यटन मंत्रालय की चल रही योजनाओं के तहत विभिन्न पहलों को मजबूत करने की योजना है।

अरविंद ने आगे कहा कि भारत 2023 में जी 20 की अध्यक्षता के दौरान खुद को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहा है। हम अपने देश में दुनिया के स्वागत में शिष्टाचार, समर्पण को सुनश्चित करते हुए अपनी सांस्कृतिक समृद्धि को सामने रखने की योजना बना रहे हैं। हम वीजा से जुड़े सुधार, यात्रा में आसानी, हवाई अड्डों पर यात्री अनुकूल आप्रवासन सुविधाएं और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए खुले नियमों सहित आवश्यक कदम उठाने की योजना बना रहे हैं और इन प्रमुख विषयों पर दो दिवसीय बैठक के दौरान विचार-विमर्श किया गया था।

2024 के लिए भारत पर्यटन क्षेत्र के लक्ष्यों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हम 2024 के मध्य तक महामारी के पहले के स्तर तक रिकवर होने का प्रयास करेंगे। देश को 2024 कर 1.5 करोड़ विदेशी यात्रियों के आगमन, सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन से 50 अरब डालर के और विदेशी मुद्रा आय में 30 अरब डालर के योगदान का अनुमान है।

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दशक में भारत के 7-9 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है और 2030 तक पर्यटन से जीडीपी में 250 अरब डालर, विदेशी मुद्रा आय में 56 अरब डालर के योगदान, पर्यटन क्षेत्र में 13.7 करोड़ नौकरियां और 2.5 करोड़ विदेशी पर्यटकों के आगमन के स्तर को हासिल किया जाना है। हम 2047 तक पर्यटन क्षेत्र में भारत की स्थिति सबसे अग्रणी देशों में सुनिश्चित करने के लिए इन लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं के अनुरूप योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सम्मेलन सत्र के अंतिम दिन पर्यटन स्थलों की मार्केटिंग और प्रचार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका, भारतीय आतिथ्य क्षेत्र में होमस्टे के उभरते महत्व, आयुर्वेद, कल्याण और चिकित्सा के लिए यात्रा, और अंत में वन और वन्यजीव पर्यटन पर सम्मेलन आयोजित किए गए। सचिव इलेक्टॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार अल्केश शर्मा, सचिव कौशल विकास और उद्यमशीलता, भारत सरकार राजेश अग्रवाल, जी 20 शेरपा अमिताभ कांत, सदस्य नीति आयोग डॉ विनोद कुमार पॉल, एडिशनल सेक्रेटरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण लव अग्रवाल, पर्यटन सचिव अरविंद सिंह, महानिदेशक पर्यटन जी. कमला वर्धन राव और मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विभागों का आपसी समन्वय जरूरी: अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। ज़िला में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के बारे में उपायुक्त कार्यालय में ज़िला विकास

समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा की जबकि लोकसभा सांसद किशन कपूर बैठक में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

केन्द्रीय मंत्री ने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की वास्तविक जानकारी ली तथा योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना अधिकारियों का मुख्य दायित्व है।

उन्होंने कहा कि अनेक क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि योजनाओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उसका लाभ समय पर पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाता है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि, बागवानी, पर्यटन तथा उद्योग लगाने में स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं। इस दिशा में अधिकारियों को सार्थक प्रोजेक्ट तैयार करके युवाओं को इन परियोजनाओं से जोड़ने के साथ स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस दिशा में कृषि, बागवानी तथा उद्योग विभाग को संयुक्त प्रयास करने चाहिए ताकि कृषि-बागवानी उत्पादन के साथ-साथ उसकी उचित खपत सुनिश्चित होने के साथ किसानों तथा बागबानों की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। उन्होंने स्थानीय किसानों को ई-मान पोर्टल से जोड़ने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि किसानों को अपने उत्पाद के बेहतर दाम मिल सकें।

अनुराग ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में टीबी रोगियों की पहचान हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान ज़िला में 220 टीबी रोगियों की पहचान होना एक गंभीर चिंतन का विषय है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक पग उठाने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान लोकसभा सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना के अर्न्तगत चल रहे विकास कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना की स्वीकृति के समय 2200 करोड़ रूपये व्यय करने का अनुमान था जोकि 1100-1100 करोड़ केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना था। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस मामले को पुन: केन्द्र सरकार के समक्ष उठा कर परियोजना के लिये धनराशि मुहैया करवाने का आग्रह किया था। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के आग्रह पर स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वन के लिये 90:10 के अनुपात में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से 550 करोड़ रूपये की परियोजनाएं वर्तमान में धर्मशाला स्मार्ट सिटी में चल रही हैं जिसमें प्रदेश सरकार का हिस्सा केवल मात्र 50 करोड़ रूपये बनता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से ही प्रदेश को पुन: विशेष राज्य का दर्जा बहाल हो पाया है।

किशन कपूर ने बताया कि मनरेगा के तहत इस वित्त वर्ष में 130 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि ज़िला में आजादी के अमृत महोत्सव पर मनरेगा के तहत 134 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं जिन में से अब तक 73 अमृत सरोवर बन कर तैयार हो चुके हैं। ज़िला की लगभग सभी पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है जिससे जहां लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है वहीं गांव भी खुशहाल हुए हैं। उन्होंने एनएच के अधिकारियों से मटौर- मक्लोड़गंज सड़क के कार्य को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला सुशासन सूचकांक में जिला कांगड़ा को प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने पर समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिये बधाई दी और बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये निरंतर बेहतर कार्य करते रहने का आहवान किया, ताकि जिला की उच्च रैंकिंग को बनाया रखा जा सके।

उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों की समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। ।

बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ खुशाल शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त गन्धर्वा राठौढ़, स्मार्ट सिटी परियोजना के एमडी प्रदीप ठाकुर, एडीएम राहुल राठौड़, ज़िला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़ सहित विभिन्न विभागों के ज़िला अधिकारी भी उपस्थित रहे।

फार्मासिस्टों से की मरीजों के मार्गदर्शन की अपील:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर सोलन जिले के कसौली से राज्य फार्मेसी परिषद के सदस्यों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान फार्मासिस्टों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और डॉक्टरों के बाद मरीज फार्मासिस्टों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि फार्मासिस्टों को पूरी सावधानी के साथ मरीजों की सेवा करनी चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर किसी भी दवा का गलत प्रभाव न पड़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि फार्मासिस्ट का काम केवल मरीजों को दवा देना ही नहीं है, बल्कि जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए मरीजों को सही सलाह देना तथा उन्हें जागरुक करना भी फार्मासिस्ट का कर्तव्य है। सभी फार्मासिस्टों को इस दिशा में कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत किया है जो राज्य की अर्थव्यवस्था और यहां के युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क की स्थापना से कच्चे माल के लिए चीन पर भारत की निर्भरता खत्म हो जाएगी और इस क्षेत्र में चीन का एकाधिकार लगभग समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे फार्मा कंपनियों को हजारों करोड़ रुपये की बचत होगी, क्योंकि उन्हें हिमाचल में कच्चा माल मिलेगा और दवाओं का निर्माण भी सस्ता होगा। इससे दवाओं की कीमतें भी कम होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में आयोजित युवा विजय संकल्प रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मेसी क्षेत्र में हिमाचल की क्षमता की प्रशंसा की है और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बल्क ड्रग पार्क से विश्व फार्मेसी के हब के रूप में हिमाचल अपनी एक अलग पहचान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का बद्दी क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बनकर उभरा है और कोरोना महामारी के दौरान बद्दी क्षेत्र में निर्मित दवाओं की आपूर्ति विश्व भर के देशों में की गई। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में 349 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है और इसके लिए करोड़ों रुपये के एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे करीब 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य फार्मेसी परिषद के पोर्टल का भी शुभारंभ किया।

इस मौके पर स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉ.राजीव सैजल ने कहा कि विश्वभर में फार्मासिस्टों के सम्मान में 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस की शुरुआत 2009 में इस्तांबुल में इंटरनेशनल फार्मास्युटिकल फेडरेशन द्वारा दुनिया के हर कोने में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में फार्मासिस्टों की भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से हिमाचल में जल्द चुनाव करवाने की मांग की

शिमला/शैल। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से हिमाचल में जल्द चुनाव करवाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल शिमला में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों के संबंध में मिला। कांग्रेस ने कहा कि अगर चुनाव देरी से करवाए जाते हैं तो इससे किन्नौर, लाहुल स्पिति, चंबा, शिमला और कुल्लू जिला में चुनाव करवाना संभव नहीं होगा। ऐसे में राज्य में जल्द चुनाव करवाना जरूरी है। यही नहीं प्रदेश में जल्द चुनाव करवाने से भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे सरकारी धन के दूरुपयोग को भी रोका जा सकेगा। हिमाचल में भाजपा सरकार अंतिम समय में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है, जबकि इनके लिए बजट का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।

कांग्रेस ने एक जगह पर लंबे अरसे से डटे अधिकारियों के तबादले भी तत्काल करने की मांग की। कांग्रेस का कहना था कि ये अधिकारी राजनीतिक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे मे इन अधिकारियों को तुरंत बदला जाना चाहिए ताकि राज्य में पारदर्शी तरीके से चुनाव संभव हो। चुनाव आयोग से यह भी मांग की कि विधानसभा चुनावों के लिए इस्तेमाल होने वाली ईवीएम के लिए उचित सुरक्षा कदम उठाए जाए और उनको कड़ी सुरक्षा में रखा जाना चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुशांत कपरेट ने कहा है कि कांग्रेस ने हिमाचल में जल्द चुनाव करवाने की मांग की ताकि बर्फबारी वाले इलाकों में चुनाव प्रभावित न हो। इसके साथ ही तीन साल से एक जगह पर डटे अधिकारियों को बदलने और मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की गई। उन्होंने कहा कि जिन हल्कों में मतदाताओं की संख्या में तेजी से बढ़ौतरी हुई है वहां पर इनकी उचित स्क्रूटनी करवाने का आग्रह आयोग से किया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग से फर्जी और डयूल वोटर्स पर भी रोक लगाने का आग्रह किया गया है। देखने में आया है कि कई विधानसभा हल्कों में डबल वोर्टस बनाए गए हैं। प्रतिनिधिमंडल में सुशांत कपरेट के अलावा कांग्रेस महासचिव यशपाल तनाइक और सचिव तरूण पाठक भी शामिल रहे।

अतुल्य एसजेवीएन @ 35' का शुमारंभ

शिमला/शैल। नन्द लाल शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन ने 24 मई 1988 को अपनी स्थापना के 35गौरवशाली वर्षो का उत्सव मनाने के लिए कारपोरेट मुख्यालय, शिमला

में आयोजित एक भव्य समारोह में 35-सप्ताह तक चलने वाले काऊंटडाउन 'अतुल्य एसजेवीएन @ 35' का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि नन्द लाल शर्मा ने एसजेवीएन की उपलब्धियों और माईलस्टोन से परिपूर्ण यात्रा के 35 वर्षो के प्रतीक स्वरूप 35 दीये प्रजवलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

नन्द लाल शर्मा ने सभी एसजेवीनाइट्स को कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बधाई दी। शर्मा ने वर्ष 2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 25000 मेगावाट और वर्ष 2040 तक 50000 मेगावाट की स्थापित क्षमता हासिल करने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की।

शर्मा ने कहा कि 'हमारे कर्मचारियों की प्रतिबद्धता से शक्ति संपन्न होकर एसजेवीएन अभूतपूर्व प्रगति के पथ पर तीव्रता से अग्रसर है, जिसके परिणामस्वरूप आज हमारे पास लगभग 42,000 मेगावाट का एक मजबूत और विविधिकृत पोर्टफोलियो है।

इस अवसर पर गीता कपूर, निदेशक (कार्मिक), ए.के.सिंह, निदेशक (वित्त) और सुशील शर्मा, निदेशक (विद्युत) भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में भारत, नेपाल और भूटान के सभी सीईओ और परियोजना प्रमुखों ने वर्चुअली भाग लिया, जबकि सभी कर्मचारियों सहित सभी विभागाध्यक्ष कारपोरेट मुख्यालय, शिमला में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का एसजेवीएन की सभी परियोजनाओं/इकाइयों और कार्यालयों में लाइव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर सेंट बीड्स कॉलेज, शिमला के छात्रों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई।

35 सप्ताह तक चलने वाले इस काउंटडाउन 'अतुल्य एसजेवीएन @ 35' के दौरान, जनता में जागरूकता उत्पन्न करने तथा साझा विजन को प्राप्त करने तथा इसे आगे बढ़ने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य के साथ सभी परियोजनाओं और कार्यालयों द्वारा विभिन्न इन-हाउस और आउटरीच गतिविधियों जैसे जागरूकता क्विज़, सेमिनार, कॉन्क्लेव, भाषण, मैराथन, सांस्कृतिक उत्सव और स्पोर्ट्स मीट आदि का आयोजन किया जाएगा। 35 सप्ताह तक चलने वाले इस समारोह का समापन 24 मई 2023 को एसजेवीएन के स्थापना दिवस पर ग्रैंड फिनाले के साथ होगा।

करोड़ो खर्चा करवाकर प्रदेश के युवाओं के लिए सिर्फ रणसिंघा छोड़ गए मोदी:गौरव शर्मा

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी ने प्रधान मन्त्री दौरे को लेकर चुटकी लेते हुए कहा की हिमाचल प्रदेश का करोड़ो खर्चा करवाकर युवाओं के लिए सिर्फ रणसिंघा छोड़ गए मोदी। आप के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा की मोदी जी ने प्रदेश में सिर्फ फिजूलखर्ची को बढ़ावा दिया है और उनका दौरा तो हो नहीं पाया पर प्रदेश की जनता का करोड़ो रुपया पानी की तरह बहा। गौरव शर्मा ने कहा की आज फ़िर भाजपा और मोदी जी ने प्रदेश के युवाओं को छला है और कोई भी घोषणा युवाओ के लिये नहीं की गयी। उन्होंने कहा कहां मोदी जी युवाओं को हर वर्ष दो करोड़ नौकरीयां देने की बात करते थे और कहां आज प्रदेश और देश का युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन्होने कहा की जो आस भाजपा ने युवाओं में मोदी के नाम से जगाई थी वो ख़त्म हो गई और भाजपा की कथनी करनी का अन्तर युवाओं को समझ आ गया है मोदी जी का दौरा बेहद निराशाजनक और सच में रिवाज बदलने वाला था।

देश से टीबी के खात्मे में सरकार को सीआईआई देगा सहयोग

शिमला/शैल। सीआईआई हिमाचल प्रदेश ने राज्य के उद्योग बिरादरी के साथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। बातचीत का

मुख्य उद्देश्य उद्योग के सदस्यों से टीबी रोगियों को अपनाकर देश से टीबी उन्मूलन में समर्थन बढ़ाने और समर्थन को उत्प्रेरित करने का अनुरोध करना था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) 2025 तक एसडीजी एंड टीबी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को लागू कर रहा है। तपेदिक की चुनौती के लिए पोषण संबंधी सहायता, रहन-सहन और काम करने की स्थिति और नैदानिक और उपचार सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि जैसे सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

सीआईआई इस देश से टीबी उन्मूलन में सरकार की इस पहल का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि टीबी एक राष्ट्रीय बोझ है और टीबी आमतौर पर समाज के सबसे अधिक आर्थिक रूप से उत्पादक आयु वर्ग को प्रभावित करता है जिसके परिणामस्वरूप काम का एक महत्वपूर्ण नुकसान होता है और टीबी रोगियों को गरीबी के जाल में धकेल दिया जाता है, सुबोध गुप्ता, सीआईआई हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा। माइक्रोटेक कंपनी, जिसके वे प्रबंध निदेशक हैं, आने वाले दो वर्षों में राज्य में टीबी उन्मूलन अभियान के लिए एक करोड़ रुपये प्रदान करेंगे। गुप्ता ने राज्य के अन्य सदस्य संघों जैसे बीबीएनआईए, पीआईए और एनआईए को इस नेक काम के लिए अपना समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया।

राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उद्योगपतियों से हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के साथ-साथ उन्हें भी आगे आकर इस कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन का मुद्दा सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित किया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के ज्यादातर देशों में टीबी का खात्मा हो चुका है लेकिन भारत में अभी भी ऐसे मरीजों की संख्या बड़ी है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक इससे मुद्र होने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि अगर टीबी के मरीजों को इलाज के लिए अपनाया जाए तो निश्चित तौर पर हम इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं।

सीआईआई के वाइस चेयरमैन गगन कपूर ने कहा, उद्योग हमेशा किसी भी राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए आगे आया है और उद्योग इस बार भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और पहले से ही कई उद्योग सदस्यों ने टीबी प्रभावित रोगियों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दी है। बातचीत के दौरान इस नेक काम का समर्थन करने के अलावा, राजेंद्र गुलेरिया, पूर्व अध्यक्ष, सीआईआई हिमाचल प्रदेश ने भी राज्य के कुछ प्रमुख मुद्दों को राज्यपाल के समक्ष उठाया जैसे कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों को रहने योग्य बनाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, और राज्य के कनेक्टिविटी में सुधार।

राज्यपाल ने युवाओं से की नशे की लत से बचने की अपील

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में

आयोजित तीन दिवसीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूथ फैस्टीवल ग्रुप-1 के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए युवाओं से नशे की लत से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि मादक द्रव्यों व नशे का सेवन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान हम सबको मिलकर ढूंढना है।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आहवान किया कि वे पहले अच्छे इंसान बनें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यवसाय जीवन में अपनाएं लेकिन उससे पहले अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम केवल 'मेमोरी टेस्ट' है। डिग्रियां केवल हमें रोजगार दे सकती हैं और यह हमें निर्धारित करना है कि हमे नौकरी पाने वाला बनना है या रोजगार देने वाला। उन्होंने अमृत काल में अपना लक्ष्य निर्धारित करने की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ें। उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने अनेक चुनौतियां हैं जिन्हें उन्हें समझना है और उनके लिए तैयार रहना है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने यूथ फैस्टीवल के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

इससे पूर्व, महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. रुचि रमेश ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा यूथ फैस्टीवल में आयोजित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने महाविद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी दी।निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं युवा कार्यक्रम निदेशालय प्रो. हरि सिंह, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, शिक्षक-अभिभावक संघ के प्रधान जे.आर. भारद्वाज, विभिन्न महाविद्यालयों के प्रभारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सुबह लिये फैसले शाम को बदल रही जयराम सरकार:अनिरुद्ध सिंह

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि जयराम सरकार अफसरशाही की सरकार है।

शिमला मे प्रैस कांफ्रेंस में अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि सरकार का एक भी फैसला अपना नहीं बल्कि सभी फैसले अफसरशाही ही ले रही है। उन्होंने जयराम सरकार को अपने फैसले पलटने वाली सरकार करार दिया और कहा कि यह सरकार सुबह फैसले लेती है और शाम को इनको बदलती है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल में करीब 200 नोटिफिकेशन बदल डाली है।

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जयराम सरकार चुनाव के नजदीक आते ही भर्तियां निकाल रही है जबकि चुनावी आचार संहिता लगने को कुछ ही दिन बाकी है। सरकार को अब युवाओं की याद आ रही है। यही नहीं सरकार ने पहले जो कुछ भर्तियां निकालीं, उनमें पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पर्चा लीक कर हजारों युवाओं के साथ धोखा किया गया। सरकार ने पहले इसकी सीबीआई जांच की बात कही लेकिन बाद में मुकर गई।

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने झूठे वादे कर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। हिमाचल में 69 एनएच बनाने की बात केंद्र की मोदी और जयराम सरकार ने की थी, लेकिन एक भी सडक के लिए सर्वे तक नहीं करवाया गया। फोरलेन की भी यही कमोबेश यही स्थिति है। परवाणु शिमला फोरलेन के कैथलीघाट से लेकर ढली तक के हिस्से पर अभी भी काम शुरू नहीं किया गया, जबकि इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों को उजाडा गया। अब इसकी अलाइमेंट ही बदल दी गई।

अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि सरकार सीमेंट कंपनियों पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। यही वजह है कि हिमाचल में सीमेंट मंहगा बेचा जा रहा है।

अनिरूद्ध सिंह ने जयराम सरकार पर कसुम्पटी विधानसभा हल्के से भेदभाव करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पांच सालों से जयराम सरकार ने उनके इलाके में कोई काम नहीं किया, उल्टे उनके शुरू किए कार्यो लटकाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि कसुम्पटी में जो भी काम हुआ है वो विधायक प्राथमिकता और नाबार्ड की योजनाओं के तहत ही हुआ है। विधायक होने के नाते इस इलाके की 14 परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए, जिसमें 12 योजनाएं मंजूरी भी उन्होंने करवाई। इन परियोजनाओं में सरकार का कोई हाथ नहीं है।

अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत के किए कार्यो पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में सड़कें चौड़ा करने के काम में गुणवतता का कोई ध्यान नहीं रखा। कसुपंटी से भेदभाव कर शिमला नगर निगम के तहत आने वाले कसुंपटी के वार्डो में एक भी काम स्मार्ट सिटी का नहीं किया।

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शिमला शहर में चौबीस घंटों पानी देने की 764 करोड़ रूपए की परियोजना पूर्व कांग्रेस सरकार ने मंजूर करवाई थी, मगर इसका काम अभी तक नहीं शुरू हुआ। हालात यह है कि आज शिमला में लोगों को कई दिनों तक पानी नहीं मिल रहा। पानी की शहर में राशनिंग लगातार की जा रही है।

उन्होने कहा कि जयराम सरकार और भाजपा शासित नगर निगम शिमला शहर में लोगों को कोई नई पार्किंग नहीं दे पाई। पूर्व सरकार के समय में एसडीए कांप्लेक्स में पार्किंग बनाने का शिलान्यास किया गया था, इसका दोबारा से शिलान्यास स्थानीय विधायक एवं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कर डाला। विकासनगर में पार्किंग का काम अब जाकर शुरू करवाया गया। उन्होंने कहा कि मल्याणा में बन रहे आईजीएमसी के फेज दो के काम को पूरा सरकार नहीं कर पाई, इसके लिए पूर्व सरकार ने धनराशि मंजूर की थी। इसके लिए अलग से वैकल्पिक सड़क बनाई जानी थी, जो कि सरकार ने नहीं बनाई। अब इस आधे अधूरे काम का उद्घाटन करने की सरकार तैयारी कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के महासचिव यशपाल तनाइक, सचिव सुशांत कपरेट और महिला कांग्रेस की महासचिव शशि ठाकुर भी मौजूद रहीं।

युवाओं की रैली में बेरोजगारी पर दो शब्द भी नहीं बोले मोदी:कांग्रेस

शिमला/शैल। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी पर दिए ब्यान को लेकर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के महासचिव यशपाल तनाइक ने कहा है कि टूरिस्ट बनाकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के दूसरे बड़े नेता हिमाचल आ रहे हैं। जिन पर करोड़ों रूपए पानी की तरह बहाकर जयराम सरकार हिमाचल को कर्ज में डूबोने का काम कर रही है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब आधा दर्जन बार हिमाचल का दौरा कर चुके हैं, यहां की सेपू बड़ी और स्वादिष्ट व्यंजनों का गुणगान करने के सिवा उनके पास हिमाचल को देने के लिए कुछ भी नहीं रहता। इसी तरह भाजपा के अन्य नेता भी है जो कि हिमाचल आकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अबकी बार भी नरेंद्र मोदी हिमाचल को निराश कर गए। मंडी में आयोजित युवा संकल्प रैली में उन्होंने युवाओं की बेरोजगारी पर दो शब्द भी नहीं बोले और नहीं आसमान छूती मंहगाई पर वे कुछ बोल पाये। यही नहीं प्रधानमंत्री ने हिमाचल के लिए कोई कोई घोषणा नहीं की, जिससे जयराम सरकार जाते जाते भी कर्ज लेने से बच जाती।

यशपाल तनाइक ने कहा कि भाजपा नेत्री रश्मिधर सूद प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी शिव अवतार मानती हैं, जो कि पानी, बारिश और तुफान में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन ये शिव अवतार थोडी सी बारिश में मंडी में प्रकट नहीं हो पाये। वर्चुअली प्रकट होकर उन्होंने जुमलेबाजी कर हिमाचल की जनता को गुमराह करने का काम जरूर किया।

राहुल और प्रियंका पर दिये ब्यान पर कांग्रेस नेता ने कहा कि इन नेताओं को अपनी पार्टी में तानाशाही नजर नहीं आ रही। मोदी और शाही की जोड़ी ने पार्टी के उन सम्मानित नेताओं को एक-एक कर पर हाशिए पर धकेला, जिन्होंने कभी भाजपा की नींव रखी थी। भाजपा में पूरी तानाशाही हावी है और सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की पार्टी बनकर भाजपा रह गई है।

यशपाल तनाइक ने कहा कि भाजपा प्रदेश में अपनी हार को सामने देखकर बुरी तरह से बौखला गई है। इसलिए वह कांग्रेस के नेताओं पर इस तरह टिक्का टिप्पणी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को आईना दिखा चुकी है। अब विधानसभा चुनावों में हिमाचल की जनता इस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या कांग्रेस में उपमुख्यमंत्री का पद निश्चित न होने से सुखराम परिवार ने थामा भाजपा का दामन

क्या भाजपा का परिवारवाद का मानक अनिल – आश्रय पर लागू नहीं होगा?
क्या अनिल अब भी महेन्द्र सिंह को राजनीतिक गाली देने का साहस दिखायेंगे?

शिमला/शैल। भले ही बारिश ने प्रधानमन्त्री का मण्डी आना रोक दिया लेकिन इस मौसम ने सुखराम परिवार की राजनीतिक अनिश्चितता के बादल साफ करते हुये भाजपा में जाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है वैसे तो अनिल भाजपा के ही विधायक हैं। भाजपा ने उन्हें मन्त्री बनाकर पूरा सम्मान दिया था। परन्तु जब 2019 के लोकसभा चुनाव में अनिल के बेटे आश्रय शर्मा ने कांग्रेस के टिकट पर मण्डी से चुनाव लड़ लिया और अनिल स्वयं न तो भाजपा और मन्त्री पद छोड पाये न ही भाजपा के लिये चुनाव प्रचार कर पाये। इस स्थिति में भाजपा और अनिल के रिश्तों में कड़वाहट आयी तथा मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद न भाजपा ने अनिल को निकाला और न ही अनिल कोई राजनैतिक नैतिकता दिखाई बल्कि इस सारे दौरान यह आरोप अवश्य बार-बार लगाते रहे की मुख्यमन्त्री को खराब करने में केवल महेन्द्र सिंह का हाथ है। अब जिस ढंग से अनिल के बेटे आश्रय को भी भाजपा में ले आये हैं उससे यह अवश्य इंगित होता है कि मण्डी में महेन्द्र सिंह को कोसने का काम सुखराम परिवार को किसी योजना के तहत मुख्यमन्त्री ने ही तो नहीं दे रखा था। क्योंकि आज सुखराम परिवार के इस तरह पाला बदलने पर पूरी भाजपा खामोश है जबकि महेन्द्र सिंह के नाम का कवर लेकर जो जो आरोप यह लोग जयराम सरकार पर लगा चुके हैं उनका जवाब देना इन्हें ही कठिन हो जायेगा। इस परिदृश्य में यदि अनिल और आश्रय के सारे राजनीतिक चरित्र का आकलन इससे भाजपा को लाभ तथा कांग्रेस को नुकसान के गणित से किया जाये तो यही सामने आता है कि जब से पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन किया तब से मण्डी में कांग्रेस को चुनावी लाभ बड़े स्तर पर नहीं हो पाया है। क्योंकि मण्डी में कांग्रेस के बड़े नामों में स्व. पंडित सुखराम के साथ कौल सिंह, गुलाब सिंह, रंगीला राम राव और महेन्द्र सिंह का बराबर लिया जाता रहा है। इनमें से गुलाब सिंह और महेन्द्र सिंह तो कांग्रेस छोड़कर हिविकां मे शामिल हो गये। 1998 में हिविंका के सहयोग से भाजपा की सरकार बनने तक अनिल शर्मा की राजनीतिक छवि पंडित सुखराम का बेटा होने से ज्यादा नहीं बन पायी है। बल्कि जब स्वास्थ्य और केस के कारण पंडित जी की सक्रियता में कुछ कमी आयी तब अनिल घर के अन्दर के विवाद को भी बाहर आने से नहीं रोक पाये। बल्कि इस दौरान जयराम के हाथों महेन्द्र सिंह को सार्वजनिक रूप से राजनीतिक गाली देने के मोहरे के रूप में यूज होने से नहीं रोक पाये। बल्कि आश्रय भी कांग्रेस में होते हुये भी प्रतिभा सिंह और कौल सिंह को कोसने का मोहरा होकर ही रह गये। क्योंकि जब आश्रय ने मण्डी में प्रतिभा सिंह के दखल पर सवाल उठाये और द्रंग से कांग्रेस टिकट की दावेदारी जताई थी तभी राजनीतिक पंडितों के लिये यह स्पष्ट हो गया था कि अब आश्रय का भाजपा में जाना कभी भी घोषित हो सकता है। बल्कि अनिल का कांग्रेस में उपमुख्यमंत्री की मांग रखना भी इसी रणनीति का हिस्सा था। जिसे कांग्रेस ने समय रहते ही समझ लिया और अस्वीकार कर दिया। इस परिपेक्ष में जब अनिल और आश्रय भाजपा के हो जाते हैं तो सबसे पहले इन्हें परिवारवाद के मानक को क्रॉस करना होगा। क्या भाजपा इनके लिये इस मानक को नजरअन्दाज कर देगी? क्या इस मानक के लिये यह लोग अपने राजनीतिक हित की आहुति देने के लिये सहमत हो जायेंगे? यदि भाजपा अनिल आश्रय के लिये परिवारवाद के सिद्धांत को नजरअन्दाज करने पर सहमत हो जाती है तो उसी गणित से यह सिद्धान्त महेंद्र सिंह और धूमल परिवारों पर कैसे लागू हो पायेगा? वैसे तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा भी अपने बेटे को विधायक या सांसद देखना चाहते हैं। बिलासपुर की कोई भी राजनीतिक गतिविधि नड्डा के बेटे की उपस्थिति के बिना पूरी नहीं होती है। दूसरी ओर अब जब अनिल और आश्रय दोनों भाजपा के हो गये हैं तो अब वह किस नैतिकता के तहत महेन्द्र सिंह के खिलाफ पहले की तरह मुंह खोल पायेंगे यह भी आने वाले दिनों का एक बड़ा सवाल होगा जिसका प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ेगा।

जन सरोकारों पर संघर्ष का स्वभाविक लाभ वामदलों को मिलना तय

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी ने जहां चार विधानसभा क्षेत्रों के लिये उम्मीदवारों की घोषणा की है वहीं पर सी.पी.एम. ने एक दर्जन क्षेत्रों के लिये उम्मीदवार घोषित कर दिये हैं। मौजूदा विधानसभा में भी सी. पी. एम. का एक उम्मीदवार है जिसकी सदन में रही वर्किंग इसका पर्याप्त प्रणाम बन जाती है कि सी.पी.एम. जन मुद्दों के प्रति कितना सजग और ईमानदार रही है। सी.पी.एम. की तुलना आम आदमी पार्टी से करना इसलिये आवश्यक हो जाती है कि आप प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा का विकल्प होने का दावा कर रही है। जबकि जन सरोकारों के मुद्दों पर सी.पी.एम. की गंभीरता तथा जन संघर्ष में भागीदारी कांग्रेस और भाजपा से कहीं अधिक रही है। आज शिक्षा को जिस तरह मौजूदा सरकार प्राईवेट सैक्टर के हवाले एक योजनाबद्ध तरीके से करती जा रही है और प्राईवेट शिक्षण संस्थानों ने फीसें बढ़ाकर करीब एक लाख तक पहुंचा दी है तब इस सब के विरूद्ध किसी ने आन्दोलन का आयोजन किया है तो इसका श्रेय केवल सी.पी.एम. को जाता है। शिक्षण संस्थाओं को बाजार

बनाने के प्रयासों का विरोध किया जाना आज पहली आवश्यकता बन चुका है। क्योंकि सरकारी स्कूलों को जानबूझकर कमजोर रखा जा रहा है बल्कि अध्यापकों की आपूर्ति करवाने के लिए उच्च न्यायालय का सहारा तक लेना पड़ा है।

अभी जब पशुओं विशेषकर गोधन में जो लम्पी रोग का प्रकोप फैला और इस दिशा में सरकार के प्रयास नहीं के बराबर सिद्ध हुये तब सी.पी.एम. के नेता और कार्यकर्ता ही प्रभावितों का दर्द बांटने के लिये उनके पास पहुंचे। कुसुम्पटी क्षेत्र जो शिमला की जलापूर्ति का एक बड़ा स्त्रोत है जब इसके बाशिंदों को पेयजल का संकट झेलना पड़ा तब इनकी समस्या को संबद्ध प्रशासन तक पहुंचाने में सी.पी.एम. नेता डॉ. तनवर ही इनके पास पहुंचे। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सी.पी.एम. नेतृत्व जनता के साथ खड़ा होने में अग्रिम रहा है। जनहित से जुड़े मुद्दों पर सत्ता के खिलाफ खड़ा होने की जो भूमिका सी.पी.एम. ने निभाई है वह विपक्ष के नाते कांग्रेस या आप नहीं निभा पायी है। जन सरोकारों पर संघर्ष के मानक पर वाम नेतृत्व से ज्यादा खरा कोई नहीं उतरता है। ऐसे में यदि जनता का समर्थन मुद्दों के मानक पर आता है तो इस बार तीसरे दल के नाम पर सी.पी.एम. का दखल विधानसभा के पटल पर संख्या बल के नाम पर बहुत प्रभावी रहेगा यह तय है। क्योंकि आप भाजपा की बी टीम होने के लांछन से मुक्त नहीं हो पायी है। भाजपा सत्ता के लिए जांच एजैन्सियों के दुरुपयोग में सारी सीमाएं लांघती जा रही है यह धारणा समाज के हर वर्ग में बहुत गहरे तक उतर गयी है। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग जांच एजैन्सियों के बढ़ते दखल से डरकर भाजपा में जाने में ही अपनी भलाई मान रहा है। इस वस्तुस्थिति का स्वभाविक राजनीतिक लाभ सी.पी.एम. को मिलना तय है।